Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES

4th August 2025

HINDI

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

केरल में ड्रोन से बीज बोने की सफल कोशिश

परंपरागत धान की खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, केरल कृषि विश्वविद्यालय (KAU) ने कुंबलंगी के पोख्कली क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से बीज छिड़काव का सफल परीक्षण किया है। यह पहल वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और फ्यूसेलेज इनोवेशन नामक कंपनी की साझेदारी में की गई।

इस तकनीक में उपयोग किए गए ड्रोन में 10 किलो तक अंकुरित बीज भर सकते हैं और यह 20 से 25 मिनट में एक एकड़ खेत में बीज छिड़क सकता है। इस प्रक्रिया से बीज की बचत होती है (लगभग 10 किलो प्रति एकड़), साथ ही मजदूरी की जरूरत भी काफी कम हो जाती है।

KAU के एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर प्रमुख डॉ. के.पी. सुधीर के अनुसार, अंकुरित बीजों का इस्तेमाल इसलिए उपयुक्त है क्योंकि वे कीचड़ भरी मिट्टी में आसानी से जम जाते हैं।

अब विश्वविद्यालय और भी बड़ी क्षमता वाले ड्रोन विकसित करने पर विचार कर रहा है ताकि बड़े खेतों में इस तकनीक का प्रयोग हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नवाचार खासकर पोख्कली और कुट्टनाड जैसे इलाकों में खेती का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, जहां पारंपरिक विधियाँ काफी मुश्किल भरी हैं।

पंजाब के किसान CHC की जगह खुद की मशीन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं

पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी पर मशीनें देने की योजना चल रही है। हालांकि, राज्य के किसान कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) से मशीनें किराए पर लेने की बजाय, खुद की मशीन खरीदना ज्यादा बेहतर समझते हैं।

साल 2020 से 2025 के बीच कुल 98,153 CRM (फसल अवशेष प्रबंधन) मशीनें सब्सिडी पर दी गईं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई मशीनें व्यक्तिगत किसानों ने खरीदीं। केवल 29,499 मशीनें ही CHC या किसान समूहों ने लीं।

यहां तक कि सरकार CHC को 80% सब्सिडी देती है, जबकि व्यक्तिगत किसानों को 50% मिलती है, फिर भी किसान निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका कारण है – CHC से समय पर मशीन न मिलना, मशीन खराब हो जाने पर रखरखाव में देरी, और कम स्टाफ।

विशेषकर 'सुपर सीडर' जैसी बहुउपयोगी मशीनें किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं, जिन्हें वे खुद रखना चाहते हैं ताकि समय पर इस्तेमाल कर सकें।

CHC द्वारा खरीदी गई मशीनों की संख्या साल 2020–21 में 15,184 से घटकर 2023–24 में सिर्फ 465 रह गई है, जो नीति और ज़मीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है।

राज्य सरकार अब इसके समाधान के लिए एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप और नई इंसेंटिव योजनाओं को अपने 2025–26 स्टबल मैनेजमेंट प्लान में शामिल करने की तैयारी कर रही है।

जलवायु अनुकूल खेती के लिए ICAR और ICRISAT की AI आधारित सलाह सेवा

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, छोटे किसानों की मदद के लिए ICAR और ICRISAT ने मिलकर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित एग्रोमेट एडवाइजरी सेवा शुरू की है। यह सेवा भारत सरकार के मानसून मिशन-III के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसमें भारतीय मौसम विभाग (IMD), IITM और CGIAR की AI4CRA नेटवर्क की भी भागीदारी है।

यह सेवा मशीन लर्निंग और रीयल-टाइम डेटा के जरिए फसलों, मौसम और मिट्टी की जानकारी को मिलाकर किसानों को स्थान और फसल के अनुसार सटीक सलाह देती है।

इसके मुख्य फीचर्स में एक AI-पावर्ड WhatsApp बॉट है जो किसानों को उनकी भाषा में व्यक्तिगत सलाह देता है। यह सिस्टम मोबाइल ऐप, IVRS और गांव के संसाधन केंद्रों के जरिए जानकारी भेजता है।

इस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र में पायलट परियोजना के रूप में की गई है और भविष्य में इसे पूरे भारत और अन्य देशों में लागू किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों तक सलाह पहुंचाना है, जिससे वे मौसम से होने वाले नुकसान से बच सकें और अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा सकें।

खेती की लागत घटाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ज़ोर

गुंटूर स्थित आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के 20वें चरण का हिस्सा था।

विशेषज्ञों ने बताया कि धान, मिर्च, चना और कपास जैसी प्रमुख फसलों की खेती पर प्रति एकड़ ₹35,000 से ₹50,000 तक खर्च आता है। ऐसे में लागत को कम करने के लिए ड्रोन तकनीक, सटीक कृषि उपकरण और कृषि विज्ञान केंद्रों से सलाह लेना जरूरी है।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की उन्नत प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया, जो जलवायु अनुकूल और लागत प्रभावी तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं।

बायो-पेस्टिसाइड्स के बढ़ते उपयोग की सराहना की गई, लेकिन साथ ही नकली और बिना लाइसेंस वाले उत्पादों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई।

ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और मशीनीकरण के बढ़ते प्रयोग को खेती की टिकाऊ आय और मज़दूरों पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम माना गया।

अरुणाचल प्रदेश बना भारत की कीवी राजधानी, बागवानी नीति 2025–35 की घोषणा

अरुणाचल प्रदेश भारत का शीर्ष कीवी उत्पादक राज्य बन गया है, जहां उत्पादन 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है और यह फल के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य भी है। राज्य ने किन्नू उत्पादन में भी देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसकी मात्रा 84,000 मीट्रिक टन है। इसके अलावा, अरुणाचल पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक बड़ी इलायची उत्पादन (4,467 मीट्रिक टन) करने वाला राज्य बन गया है। एक बड़ी निर्यात सफलता के तहत डांबुक की संतरे अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, तक पहुंच रहे हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास और अवसरों की वृद्धि को दर्शाता है।

इन्हीं उपलब्धियों के साथ राज्य ने बागवानी नीति 2025–35 की घोषणा की है, जो कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास, मूल्य संवर्धन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह नीति केवल कृषि का समर्थन नहीं बल्कि किसानों की गरिमा और संभावनाओं में निवेश के रूप में देखी जा रही है। ये उपलब्धियां राज्य की उपजाऊ भूमि और किसानों की मेहनत का प्रमाण हैं।

कश्मीर में सेब क्रांति: हाई-डेंसिटी बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं से बागवानी क्षेत्र में बदलाव

जम्मू-कश्मीर में बागवानी क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है, जो प्रतिवर्ष ₹5,000 करोड़ का योगदान देता है और 7 लाख से अधिक परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। 236 निजी नर्सीरियों से 13 लाख पौधों का उत्पादन हो रहा है। सेब की उत्पादकता वर्तमान में 10 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जिसे हाई-डेंसिटी प्लांटेशन योजना के तहत 45 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की संभावना है। यह 100% केंद्रशासित निधि योजना 12 फलों पर केंद्रित है और 5 वर्षों में 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखती है।

इसके साथ, पीएम एफएमई (PMFME) योजना "एक जिला एक उत्पाद" (ODOP) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण आधारित पूंजी सहायता, ब्रांडिंग, विपणन और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसमें एफपीओ, एसएचजी और सहकारी संस्थाओं को बुनियादी ढांचे, तकनीकी उन्नयन और संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। अखरोट, चेरी और उन्नत किस्मों जैसे अम्बरी और रेड फूजी की खेती से क्षेत्र में सतत बागवानी विकास और ग्रामीण समृद्धि को बल मिल रहा है।

बागवानी निर्यात में वैश्विक हब बनने की दिशा में उत्तर प्रदेश की पहल

उत्तर प्रदेश ने बागवानी निर्यात को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया है। लखनऊ में राज्य बागवानी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। बैठक में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने, उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और वैश्विक ब्रांडिंग पर जोर दिया गया। हाल ही में आयोजित मैंगो फेस्टिवल 2025 को एक सफल प्रयास के रूप में देखा गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आमों को वैश्विक पहचान मिली और अब ये रूस में ₹800 प्रति किलो तक बिक रहे हैं।

यह भी बताया गया कि आगामी जेवर एयरपोर्ट से हवाई निर्यात को नई गति मिलेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी। बैठक की एक प्रमुख उपलब्धि एएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना रहा, जो निर्यातकों को एकल खिड़की समाधान प्रदान करेगा। ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने और राज्य के बागवानी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अहम हैं।

त्रिपुरा में ट्रेस्प योजना के तहत जीआईएस तकनीक के माध्यम से महिला कृषकों को सशक्त बनाने की पहल

त्रिपुरा के बागवानी विभाग ने ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने और आदिवासी महिला कृषकों को समर्थन देने के उद्देश्य से विश्व बैंक समर्थित ट्रेस्प (TRESP) परियोजना के अंतर्गत जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) तकनीक की शुरुआत की है। यह पहल राज्य के 23 आदिवासी बहुल ब्लॉकों में कृषि योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हाल ही में अगरतला में जीआईएस मैपिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें इन ब्लॉकों में कार्यरत अधिकारियों को भागीदारी के साथ क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जीआईएस तकनीक के माध्यम से किसान फील्ड स्कूलों के जरिये अपनाए जा रहे आधुनिक कृषि तरीकों की निगरानी और महिला उत्पादक समूहों को समयबद्ध सहायता देना अब और भी आसान होगा। प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, और सभी 23 ब्लॉकों से प्रारंभिक जियो-मैपिंग डेटा एक सप्ताह के भीतर संकलित किया जाएगा। यह डिजिटल पहल महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ बागवानी विकास की दिशा में राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कृष्णा मिल्क यूनियन देगा ₹13 करोड़ का बोनस, शुरू करेगा किसानों के लिए नई सहायताएं

कृष्णा मिल्क यूनियन ने 2025–26 वित्तीय वर्ष के लिए डेयरी किसानों को ₹13 करोड़ का बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच की दूध आपूर्ति के लिए है और अगस्त महीने में वितरित किया जाएगा। यह निर्णय यूनियन की संचालन समिति की 31 जुलाई 2025 को हुई बैठक में लिया गया।

मिल्क यूनियन लगातार किसानों को सबसे अधिक दुग्ध खरीद मूल्य प्रदान करने और नियमित रूप से बोनस देने में अग्रणी रहा है। किसानों की भलाई और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में यूनियन एक और महत्वपूर्ण पहल कर रहा है—सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज को रियायती दर पर उपलब्ध कराना। जहां बाजार में इसकी कीमत ₹150 प्रति डोज है, वहीं कृष्णा जिले के किसानों को यह केवल ₹50 में मिलेगा और शेष ₹100 का खर्च यूनियन उठाएगा। यह योजना पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इसके अलावा, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए दो नए वेटरनरी हॉस्टल भी स्थापित किए जाएंगे—एक पेदाकल्लेपल्ली (अवनीगड्डा मंडल) और दूसरा मुनगाचेरला (नंदिगामा मंडल) में।

पशुपालन को मिला कृषि के समकक्ष दर्जा, महाराष्ट्र में नीति में बड़ा बदलाव

ग्रामीण आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने पशुपालन क्षेत्र को कृषि के समकक्ष दर्जा देने की घोषणा की है। यह निर्णय 1 अगस्त 2025 को जारी एक सरकारी संकल्प (GR) के माध्यम से लिया गया, जिससे पशुधन आधारित उद्यमों को अब फसल उत्पादन के समान लाभ प्राप्त होंगे।

इस फैसले के तहत पशुपालन इकाइयों को कृषि दर पर विद्युत शुल्क, सोलर पंप और उपकरणों पर सब्सिडी, ग्राम पंचायत कर में एकरूपता, और कार्यशील पूंजी ऋण पर 4% तक ब्याज अनुदान जैसे लाभ मिलेंगे—जो पहले इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं थे।

यह नीति विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर की इकाइयों पर केंद्रित है, जैसे कि 25,000 ब्रॉयलर या 50,000 लेयर पक्षियों तक की पोल्ट्री फार्म, 100 दुधारू पशुओं तक के पशु शेड, 500 बकरियों/भेड़ों और 200 सूअरों तक के फार्म।

यह कदम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने और समूह-आधारित पशुपालन जैसे आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। राज्य में 60 लाख से अधिक परिवार पशुपालन से जुड़े हैं और यह क्षेत्र कृषि आय में 24% का योगदान देता है। इस नीति परिवर्तन से ग्रामीण विकास और निवेश को बल मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा में पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत 16.77 लाख किसानों को ₹353 करोड़ वितरित

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20 वीं किस्त के तहत हरियाणा के 16.77 लाख किसानों को ₹353 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। यह घोषणा करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई, जो प्रधानमंत्री के वाराणसी से संबोधन के साथ सीधा प्रसारित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि केवल करनाल जिले के 80,794 किसानों को आधार-लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹18 करोड़ की राशि प्रदान की गई। NDRI के ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में किसान एवं उनके परिवार कार्यक्रम में शामिल हुए।

2019 में शुरू की गई PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, जिससे वे बीज, उर्वरक आदि कृषि इनपुट्स की लागत को पूरा कर सकें। अब तक हरियाणा में इस योजना के तहत ₹6,563.67 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार के कार्यक्रम अंबाला के KVK दमला और यमुनानगर में भी आयोजित किए गए, जो राज्य सरकार की किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और तकनीकी एकीकरण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

एनडीआरआई और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने सतत डेयरी अनुसंधान के लिए मिलाया हाथ

पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, ICAR–नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक अनुसंधान टीम ने एनडीआरआई का दौरा कर भविष्य की शोध योजनाओं पर चर्चा की। पशुधन से होने वाला मीथेन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। इस साझेदारी के तहत डेयरी दक्षता, गोबर प्रबंधन, पर्यावरणीय निगरानी और पशु कल्याण तकनीकों में नवाचार के माध्यम से समाधान विकसित किए जाएंगे।

कॉर्नेल के डॉ. जोसेफ डब्ल्यू. मैकफेडेन ने भारत की जलवायु-सहिष्णु देसी नस्लों की प्रशंसा की और छोटे किसानों के लिए सतत डेयरी प्रणालियों पर संयुक्त शोध में रुचि जताई। 103 वर्षों की विरासत वाला एनडीआरआई 1,076 डेयरी पशुओं का पालन करता है और प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध क्षमता वाला वाणिज्यिक संयंत्र संचालित करता है। संस्थान पशु क्लोनिंग, जीनोम संपादन और स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक में अग्रणी रहा है।

इस सहयोग के तहत ₹1.20 करोड़ की लागत वाली एक संयुक्त शोध परियोजना भी शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य रुमेन पोषण मॉडल और चारा पुस्तकालय विकसित करना है।

AAU, खानापाड़ा में पांच दिवसीय वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन पर कौशल प्रशिक्षण

असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU), खानापाड़ा के पशु चिकित्सा विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा 21 से 25 जुलाई, 2025 तक वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन पर पांच दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण सिक्किम पशुपालन विकास बोर्ड (SLDB), पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, सिक्किम सरकार के आर्थिक सहयोग से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य सिक्किम में डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाना था।

प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में AAU और SLDB के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ. हिरण्य कुमार भट्टाचार्य, सह निदेशक (विस्तार शिक्षा), ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। डॉ. प्रभोध बोरा, निदेशक अनुसंधान (पशु चिकित्सा), ने व्यावहारिक कौशल आधारित प्रशिक्षण की महत्ता को रेखांकित किया। वहीं, डॉ. तेनजिंग लोबसांग भूटिया, पशु चिकित्सा अधिकारी, SLDB, ने डेयरी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, संवाद सत्र और फील्ड विजिट आयोजित की गईं, जिसमें प्रतिभागियों ने सोनापुर के एक डेयरी फार्म और कोईनाधारा, गुवाहाटी स्थित एक दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का दौरा किया। कुल 20 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। समापन दिवस पर पोस्ट-ट्रेनिंग मूल्यांकन और प्रमाणपत्र वितरण हुआ। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत लाभकारी बताया और ऐसे और कार्यक्रमों की मांग की ताकि क्षेत्र में डेयरी विकास को गति मिल सके।

दूध की मांग बढ़ने के बीच गोवा में बनी हुई है भारी कमी, संरचनात्मक चुनौतियां बनी बाधा

वित्त वर्ष 2024–25 में गोवा की दूध आपूर्ति उसकी दैनिक मांग से काफी कम बनी हुई है। राज्य में औसत मासिक दुग्ध संग्रहण मात्र 37,986 लीटर है, जबकि रोज़ाना की मांग 48,818 लीटर है। जून 2025 तक यह आंकड़ा और गिरकर 35,653 लीटर प्रति माह रह गया, जबकि दैनिक मांग 45,380 लीटर पर बनी हुई है।

इस कमी को पूरा करने के लिए गोवा को पड़ोसी राज्यों से दूध आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। सब्सिडी योजनाओं के बावजूद राज्य में लघु स्तर की डेयरी गतिविधियों में खास प्रगति नहीं हुई है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। इसके पीछे कई कारण हैं—युवाओं की पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में रुचि, बंटे हुए भू-स्वामित्व, सामुदायिक डेयरी का अभाव और बढ़ती शहरीकरण।

विशेषज्ञों का मानना है कि गोवा की स्थिति भारत के डेयरी तंत्र में गहरे समावेशन की जरूरत को दर्शाती है। राज्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में दूध की कमी को दूर करने के लिए अंतरराज्यीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना, सहकारी और सामुदायिक डेयरी मॉडल को बढ़ावा देना, तथा चारा और पशु सहायता में सुधार आवश्यक है।

कर्नाटक में ICRISAT ने गर्मी सहनशील अरहर किस्म का परीक्षण शुरू किया

ICRISAT ने उत्तर कर्नाटक के बंटनूर गाँव (बागलकोट जिले) में दुनिया की पहली गर्मी सहनशील अरहर किस्म ICPV 25444 की फील्ड ट्रायल की शुरुआत की है। यह किस्म गर्मी के मौसम में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और 45°C तक के तापमान को सह सकती है। साथ ही यह फसल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है।

यह किस्म कर्नाटक राज्य बीज निगम, राज्य कृषि विभाग और धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित की गई है। किसान हनमंथ मिरजी ने अपने खेत में इसका परीक्षण शुरू किया है और बताया कि यह किस्म पतली डंठलों और एकसमान पकने की वजह से मशीन से कटाई के लिए उपयुक्त है।

इस किस्म में कीट प्रतिरोध, तेज विकास, और उच्च दाना उत्पादन जैसे गुण भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किस्म भारत की अरहर उत्पादन में मदद करेगी, जिससे आयात कम होगा और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।

अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा देने की दिशा में "सश्वत मिठास" पहल

"सश्वत मिठास" पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI) और UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में सतत (सस्टेनेबल) गन्ना खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 431 किसानों से बातचीत की गई है, जो 66 असंगठित और 3 संगठित किसान समूहों से जुड़े हैं। इनसे मिली जानकारियों के आधार पर गांवों में प्रदर्शन प्लॉट (डेमो प्लॉट) बनाए गए हैं, जहाँ पानी की बचत, मिट्टी की सेहत और जैविक खाद के उपयोग जैसी बेहतरीन तकनीकों को दिखाया जा रहा है।

किसानों की भागीदारी और आपसी सीख को बढ़ाने के लिए टीम ने 50 किसान बैठकें, 8 फील्ड डे और 70 स्थानीय कृषि विक्रेताओं के साथ संवाद किया है। इन कार्यक्रमों के दौरान किसान विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और जलवायु के अनुकूल खेती की विधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।

यह पहल खेतों पर प्रयोग, हाथों-हाथ प्रशिक्षण और विभिन्न पक्षकारों की भागीदारी के माध्यम से किसानों को पर्यावरण के अनुकूल, संसाधन-संरक्षण करने वाली तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका उद्देश्य गन्ने की उपज बढ़ाने के साथ-साथ अयोध्या क्षेत्र में एक टिकाऊ और दोहराए जा सकने वाला मॉडल विकसित करना है।

ईस्कॉर्ट्सकुबोटा के सहयोग से सीईएफएमआई ने कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया

सेंटर ऑफ फार्म मेक्नाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने ईस्कॉर्ट्सकुबोटा लिमिटेड के सहयोग से 21 से 23 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बोर्ड सदस्यों और सीईओ के लिए तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना था।

प्रशिक्षण के पहले दिन एफपीओ के लिए बेहतर संचालन मॉडल, बोर्ड की जिम्मेदारियाँ, संगठनात्मक संरचना और पारदर्शी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा की गई। दूसरे दिन प्रतिभागियों ने ट्रैक्टर, उसके अटैचमेंट और अन्य उन्नत कृषि यंत्रों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया और संचालन तकनीक, सुरक्षा उपायों व नियमित रखरखाव के बारे में सीखा। अंतिम दिन एग्रीबिजनेस फाइनेंसिंग पर फोकस रहा, जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने की रणनीतियाँ शामिल थीं।

यह कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा संचालित कक्षा सत्रों, जीवंत प्रदर्शन और आपसी चर्चा के माध्यम से आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को नई तकनीकें सीखने, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि व्यवसाय को अपनाने में मदद मिली। प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी एफपीओ को प्रमाण पत्र दिए गए, जो उनके यंत्रीकरण और सतत विकास की दिशा में बढ़े कदम को दर्शाते हैं।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india